

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर
पीठासीन अधिकारी:- श्री ए.एच.गौरी आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या: 63/2017

दिनांक 27.12.2019

विकास अधिकारी पंचायत समिति लूणकरणसर जिला बीकानेर

निगरानीकर्ता

बनाम

1. मूलीदेवी पत्नी जेठाराम जाट जाति जाट निवासी वार्ड नं. 08, तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर,
2. ग्राम पंचायत लूणकरणसर जरिये सरपंच रफीक मालावत

गैरनिगरानीकर्ता

उपस्थिति:-

- 1- श्री संदीप स्वामी - अभिभाषक निगरानीकर्ता
- 2- अप्रार्थीपक्ष अनुपस्थित ।

आदेश

1. यह निगरानी राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत लूणकरणसर द्वारा जारी अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 38, पट्टा बही संख्या 192 दिनांक 07.02.2014 किये गये पट्टे को निरस्त किये जाने के सन्दर्भ में इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. निगरानी प्रस्तुत होने पर मामला दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया व मूल रिकार्ड मंगवाया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद तामील नोटिस अनुपस्थित रहने के कारण उनके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा की जाकर प्रार्थी पक्ष की मामले के गुणावगुण पर बहस सुनी गई।

3. निगरानीकर्ता प्रार्थी की तरफ से उनके अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत लूणकरणसर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में लूणकरणसर में पट्टा, पट्टा संख्या 38, पट्टा बही संख्या 192 दिनांक 07.02.2014 को जरिये संकल्प संख्या 3 दिनांक 06.02.2014 को कुल तादादी 675 वर्गगज का जारी किया गया। उक्त पट्टा, पट्टा बही संख्या 192 पर दर्ज है। तत्पश्चात् अनेक शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए माननीय जिला कलक्टर कार्यालय के आदेश संख्या सीबी-2015/7166-70 दिनांक 23.03.2015 के क्रम में ग्राम पंचायत लूणकरणसर के तत्कालीन सरपंच व सचिव द्वारा पट्टे बनाने में बरती गई अनियमितता की जांच हेतु एक जांच कमेटी गठित की गई जिस कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए गये पट्टों में अनेक अनियमिता पाये जाने पर पट्टों को निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। उक्त पट्टों में उक्त पट्टा संख्या 38, पट्टा बही संख्या 192 में पंचायत राज अधिनियम 1993 के नियम 157(2) के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नियम



की प्रमाणित प्रति दिनांक 2.2.17 को प्रार्थी को प्राप्त हुई। नकल प्राप्ति की दिनांक से निगरानी अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारीशुदा पट्टा संख्या 38, पट्टा बही संख्या 192 दिनांक 07.02.2014 को निरस्त फरमाने का आदेश फरमाया जावे।

4. हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया व इस मामले से संबंधित मूल रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत निगरानी अप्रार्थी संख्या 1 को पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत 25 वर्ष पुराना कब्जा मानते हुवे विनिमितीकरण कर पट्टा संख्या 38, दिनांक 07.02.2014 जारी किया है। जिसकी शिकायत होने पर जांच कमेटी जिसमें उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लूणकरणसर तथा नायब तहसीलदार लूणकरणसर के द्वारा संयुक्त रूप से जांच कर इस पट्टे को सरपंच द्वारा नियम विरुद्ध जारी किया जाना पाया है। जिसके आधार पर विकास अधिकारी पंचायत समिति, लूणकरणसर के द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। पट्टे की मूल पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसमें वर्ष अंकित नहीं किया है जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 ने कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए तीन पंचों की एक कमेटी गठित की। शपथ पत्र स्वयं प्रार्थी एवं पड़ौसी का प्राप्त किया गया जिसमें कब्जा पिछले कई वर्षों से होना अंकित किया। इसके अतिरिक्त साक्ष्य के तौर पर अन्य कोई दस्तोवज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा विनियमितीकरण स्थल पर हो प्रमाणित नहीं होता। साथ ही विनिमित किया गया क्षेत्रफल 675 वर्गगज है जो कि पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157(1) में वर्णित अधिकतम सीमा 300 वर्गगज से अधिक होने से नियमों के विपरीत है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस मामले में तत्कालीन सरपंच व सचिव ग्राम पंचायत लूणकरणसर द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में वर्णित प्रावधानों की पूर्णतया उल्लंघन कर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में भूमि का पट्टा जारी किया गया है वह खारिज योग्य है। लिहाजा प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत लूणकरणसर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया, पट्टा क्रम संख्या 38, बुक संख्या 192 दिनांक 07.02.2014 निरस्त किया जाता है।

6. निर्णय आज दिनांक 27 दिसम्बर 2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ए.एच.गौरी)
अतिरिक्त कलेक्टर, बीकानेर
आति. जिला कलेक्टर
(प्रशासन), बीकानेर